

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4844
गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु

फ्रांस के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग

4844. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री चंद्र शेखर साहू:

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री विद्युत बरन महतो:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का फ्रांस के साथ नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने उक्त एमओयू के अंतर्गत शामिल होने वाले संभावित क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सौर, पवन, हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा से संबंधित फ्रांसीसी तकनीकों के उपयोग के बाद भारत में नवीकरणीय ऊर्जा किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है;
- (घ) क्या भारत 2030 तक 450 गीगावाट के स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में समयबद्ध तरीके से उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (च) नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर राज्य-वार क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

- (क) से (ग): दिनांक 28.01.2021 को नई दिल्ली में फ्रांस गणराज्य के इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्रालय और भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन निम्नलिखित क्षेत्रों में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगा:

क) सौर

ख) पवन

ग) हाइड्रोजन

घ) बायोमास

ड) आपसी सहमति से कोई अन्य क्षेत्र

समझौता जापन के अंतर्गत किए जाने वाले क्रियाकलापों में भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और स्थापना में योगदान दिया जाएगा।

(घ) और (ड): जी, हाँ। भारत सरकार ने देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- i. ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
- ii. 30 जून, 2023 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों और हानियों को माफ करना;
- iii. वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री की घोषणा करना;
- iv. लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) आधार पर भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना;
- v. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं;
- vi. अक्षय विद्युत की निकासी हेतु हरित ऊर्जा गलियारा योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना;
- vii. सौर फोटोवोल्टेक प्रणाली/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों की अधिसूचना;
- viii. निवेशों को आकर्षित करने और इसके लिए सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना;
- ix. ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश;
- x. सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(च) वर्ष 2020-21 के दौरान अभी तक स्वीकृत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं/क्षमताओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

‘फ्रांस के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 25.03.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4844 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2020-21 के दौरान स्वीकृत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं/क्षमताओं का विवरण

सौर पार्क (23.03.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	सौर पार्क	क्षमता (मेगावाट)
1	हिमाचल प्रदेश	काजा सौर पार्क	1000
2	केरल	फ्लोटिंग सौर पार्क	50
3	मध्य प्रदेश	ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क	600
4		छतरपुर सौर पार्क	950
5		मोरेना सौर पार्क	1400
6		बरेठी सौर पार्क	550
7	ओडिशा	फ्लोटिंग सौर पार्क	100
8	उत्तर प्रदेश	जालौन सौर पार्क	1200
9		ललितपुर सौर पार्क	600
10		झांसी सौर पार्क	600
		मिरजापुर में सौर पार्क	100
कुल			7150

सौर रूफटॉप (23.03.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	आन्ध्र प्रदेश	25
2	असम	2
3	बिहार	20
4	चंडीगढ़	70
5	गोवा	80
6	गुजरात	492
7	हरियाणा	25
8	झारखंड	50
9	कर्नाटक	312
10	केरल	200
11	लक्षद्वीप	10
12	महाराष्ट्र	502
13	मणिपुर	1
14	मेघालय	70
15	मिजोरम	1
16	नागालैंड	3.8
17	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9.5
18	पुडुचेरी	25
19	पंजाब	50
20	तमिलनाडु	50
21	तेलंगाना	25

22	उत्तराखंड	26
23	पश्चिम बंगाल	50
	कुल	2099.3

पीएम-कुसुम (23.03.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	घटक-क (मेगावाट)	घटक-ख (संख्या)	घटक-ग (संख्या)	
				व्यक्तिगत पंपों का सौरीकरण	फीडर स्तर का सौरीकरण
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	50000
2	अरुणाचल प्रदेश	0	50	0	0
3	असम	0	1000	500	0
4	छत्तीसगढ़	30	20000	0	0
5	दिल्ली	62	0	550	0
6	गुजरात	500	3424	7000	500
7	गोवा	50	200	7000	0
8	हरियाणा	65	37000	468	0
9	हिमाचल प्रदेश	20	1550	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	5	5000	0	0
11	झारखंड	50	11000	500	10000
12	कर्नाटक	500	10500	1000	100000
13	केरल	40	100	100	2000
14	लद्दाख	0	600	0	0
15	मध्य प्रदेश	300	60000	0	50000
16	महाराष्ट्र	500	100000	0	100000
17	मणिपुर	0	150	0	0
18	मेघालय	5	700	0	10000
19	नागालैंड	0	50	0	0
20	ओडिशा	500	6000	0	0
21	पुडुचेरी	7	0	0	0
22	पंजाब	220	9500	0	25000
23	राजस्थान	1200	75000	37500	0
24	तमिलनाडु	75	6500	20000	0
25	तेलंगाना	500	0	0	65000
26	त्रिपुरा	5	3900	2600	0
27	उत्तर प्रदेश	225	23000	0	30000
28	उत्तराखंड	0	0	200	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	700	0
	कुल	4859	375224	78118	442500

बायोमास विद्युत और खोई सह-उत्पादन (23.03.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	आन्ध्र प्रदेश	1.39

2	बिहार	12.9
3	हरियाणा	14.5
4	कर्नाटक	63
5	मध्य प्रदेश	1.99
6	महाराष्ट्र	74.4
7	ओडिशा	0.8
8	पंजाब	8.4
9	तेलंगाना	2.0
10	उत्तर प्रदेश	6.75
11	पश्चिम बंगाल	4.2
	कुल	190.33

अपशिष्ट से ऊर्जा (23.03.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	आन्ध्र प्रदेश	30.96
2	गुजरात	33.72
3	हरियाणा	0.88
4	कर्नाटक	0.23
5	महाराष्ट्र	1.67
6	तमिलनाडु	2.21
7	तेलंगाना	1.17
8	उत्तर प्रदेश	1.31
9	पश्चिम बंगाल	0.36
	कुल	72.50

बायोगैस विद्युत (ऑफ-ग्रिड) (23.03.2021 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	आकार (किलोवाट)
1	तमिलनाडु	75
2	पंजाब	40
3	गुजरात	33.70
4	हरियाणा	150
5	मध्य प्रदेश	37
6	महाराष्ट्र	533.5
7	ओडिशा	130
8	आन्ध्र प्रदेश	24
9	तेलंगाना	472
10	उत्तर प्रदेश	236
	कुल	1731.2
